सुविचार
भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है।

# दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

खुशी
यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह यह है कि हम भूल चुके हैं कि हम एक-दूसरे के हैं

कुल पृष्ठ 20+4= 24 | मूल्य ₹ 5.00 | वर्ष 11, अंक 214

bhaskar.com | नई दिल्ली, शुक्रवार 02 फरवरी, 2018 | फाल्गुन कृष्ण पक्ष-2, 2074 | 12 राज्य | 67 संस्करण

# कहीं खुशी-कहीं गम वाला बजट

*गाजियाबाद। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज संसद में नए वित्त वर्ष का बजट पेश किया। बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। इस संबन्ध में दैनिक भास्कर ने शहर के उधमियों से बातचीत की, सभी लोगो ने बजट की प्रशन्सा करते हुए इसे आम जनता का बजट करार दिया है। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश।*

## केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया

सरकार ने देश की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए 50 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख दिलचस्पी दिखाई है। एग्रीकल्चर क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखा गया और साथ ही एमएसएमई यमाइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेजद्ध के टैक्स दायरे के विस्तार से राहत मिलेगी। रियल एस्टेट क्षेत्र को एक प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन बेहतर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी विकासशील क्षेत्रों में अव्यावसायिक मांग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

**अभिषेक बंसल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पैसिफिक ग्रुप**

आज के आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे तौर पर तो कोई लाभ नहीं मिलाए लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनसे आने वाले समय में सेक्टर को फायदा पहुँच सकता है। वर्तमान सरकार द्वारा यह अंतिम पूर्ण संघीय बजट प्रस्तुति थी, जो रियल्टी क्षेत्र के लिए मिश्रित बैग के साथ बाहर आई। चूँकि यह बजट रेरा और जीएसटी के आने के बाद का पहला बजट है तो हमने यह उम्मीद लगायी थी कि सरकार द्वारा सेक्टर के लिए और भी बेहतर कदम उठाये जायेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग के अलावा इस बजट में रियल्टी सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं रहा।

**मनु गर्ग, प्रेसिडेंट, क्रेडाई गाजियाबाद**

हम यूनियन बजट 2018.19 का स्वागत करते हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जोर देने के उद्देश्य से 2022 तक सभी के लिए आवास के सपने को पूरा करने का लक्ष्य है। एक बार फिर सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फण्ड का प्रस्ताव इस क्षेत्र को और भी मजबूती देगा और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ घर बनाने का मिशन 2022 तक सबके घर होने का सपना पूरा करने में कारगर साबित होगा। इसके साथ ही पूरे देश में रोडवेज के विस्तार से जिन क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया गया उसका भी विकास होगा।

**प्रदीप अगरवाल, को.फाउंडर और चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल**

## इंफ्रास्ट्रक्चर व जॉब पर फोकस

केंद्रीय बजट 2018.19 ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और जॉब के अवसरों को बढ़ाने पर काफी जोर दिया है। हालाँकि, इस बार रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे तौर पर फायदा नहीं हुआ, लेकिन 4 लाख किलोमीटर सडकों का विकास और ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से टियर 2 और 3 शहरों को सेक्टर में अलग पहचान मिलेगी । साथ ही आने वाले समय में इन क्षेत्रों में घरों की मांग और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा।

**गौरव गुप्ता, डायरेक्टर, एसजी एस्टेट्स**

इस साल के यूनियन बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार द्वारा यह कदम देश के विकास के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार के 2022 तक के हाउसिंग फॉर आल योजना के लिए अच्छे फण्ड प्रदान करने की भी बात कही जो सराहनीय है। हालाकि हमने यह उम्मीद की थी कि रियल एस्टेट क्षेत्र में रेरा और और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण एक्ट लागू होने के बाद इस साल के बजट में और भी नए संशोधन किये जायेंगे।

**मनोज गौर, वाईस प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल और एमडी, गौर्स ग्रुप**